

Notes by Akhilesh Kumar

J k college Biraul Darbhanga

YouTube :A commerce Education

Notes by Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)

J K College Biraul Darbhanga

Department of commerce

L.N.M.U B. Com part. 1 Subsidiary paper -1 Business Economics and Environment unit-6 Business Environment

वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की अवधारणा (CONCEPT OF GLOBALIZATION, LIBERALIZATION AND PRIVATIZATION)

उदारीकरण का अर्थ (Meaning of Liberalization): ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है।

उदारीकरण वह आर्थिक सुधार है जिसका उद्देश्य भारतीय व्यापार और उद्योग को सभी अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों से मुक्त करना था। वे लाइसेंस-परमिट-कोटा राज के अंत का संकेत देते हैं।

परिभाषा: उदारीकरण किसी भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राज्य कुछ निजी व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। उदारीकरण तब होता है जब किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाता था, जिसे अब प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, या जब सरकारी नियमों में ढील दी जाती है। आर्थिक उदारीकरण अर्थव्यवस्था में राज्य की भागीदारी की कमी है।

उदारीकरण के उद्देश्य (OBJECTIVES OF LIBERALIZATION): उदारीकरण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना होता है भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है उसका आर्थिक शब्दावली में नाम ढाचागत समायोजन कार्यक्रम है उदारीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- कृषि क्षेत्र का विकास करना ।
- प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को बढ़ावा देना ।
- आर्थिक विकास की रुकावट को दूर करना ।
- बाजार की शक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करना ।
- व्यवसाय के क्षेत्र में सरकारी तथा नोकरशाही हस्तक्षेप को कम करना ।
- सूचना एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करना ।
- उत्पादकता में सुधार लाना ।
- देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना ।
- अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना ।
- देशी बाजारों का विकास करना ।

- प्रबन्धकीय कार्यछमता एवं निष्पादन मर सुधार लाना ।
- देश का व्यापार सन्तुलन बनाये रखना ।
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना ।
- संसाधनों के विश्वव्यापी आधार पर स्वतंत्र बहाव को प्रोत्साहित करना ।
- आर्थिक कल्याण में वर्धि करना ।
- प्रतिबन्धो को हटाने के परिणामस्वरूप सरकारी आय में आने वाली कमी को दूर करना ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अनावश्यक एकाधिकार को समाप्त करना ।
- बीमार सार्वजनिक क्षेत्र में गतिशीलता और कुशलता लाना ।
- लालफीताशाही, अछमता तथा संसाधनों के अपव्यय को रोकना ।
- संसाधनों के विश्वव्यापी आधार पर स्वतन्त्र बहाव को प्रोत्साहन करना ।

उदारीकरण के दोष (DISADVANTAGES OF LIBERALIZATION)

- **सुधार की धीमी गति** (Slow Pace of Growth) : उदारीकरण द्वारा सुधार की गति अत्यन्त धीमी हुई है।
- **आर्थिक असमानता** (Economic Inequality) : उदारीकरण का लाभ देश के साधन सम्पन्न वर्ग को मिलेगा और स्वचालन से श्रमिक बेकार होंगे अतः इससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी ।
- **बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव** (Increasing Impact of Multinational Companies) : उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ेगा और स्वदेशी एवं स्वावलम्बन महत्वहीन हो जायेगा ।
- **उदारीकरण से स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव** (Unfavorable Impact on Stability of Liberalization) : उदारीकरण से स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा आघात पहुँच सकता है ।
- **विलासिता की वस्तुओं का आयत** (Import of Luxury Goods) : उदारीकरण के परिणामस्वरूप विलासिता की वस्तुओं के आयत में वर्धि होना अच्छा सकेत नहीं है ।
- **कृषि नीति में सुधार पर ध्यान नहीं** (Ignorance on Improvement in Agriculture Policy) : कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिन्दु है

अतः कृषिगत अर्थव्यवस्था को विशेष ध्यान देना चाहिए कृषि के लिए उदारीकरण में नवीन नीति न अपनाना दुर्भाग्य पूर्ण है ।

- **लाभदायकता में कमी** (Lack of Profitability) : उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों की लाभदायकता में कमी आयी है ।
- **विदेशी ऋणों में वर्धि** (Increasing foreign Debts) : भारत की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और ऋणदाता देशों का प्रभाव बढ़ा एवं विदेशी ऋणों में वर्धि दृष्टिगोचर हो रही है ।